बिहार विधान परिषद

(193 बिहार विधान परिषद् का शीतकालीन सत्र)

26 नवम्बर 2019

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - Education Minister - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य विधि].

22

खरीदारी पर विचार

*24 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना स्थित एन.एम.सी.एच. में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को एडवांस सर्जरी में अपग्रेड करने के लिए लाखों रुपये की लागत से खरीदी गयी सी-आर्म मशीन, महज एक ऑपरेशन टेबुल के अभाव में बेकार पड़ी है, जिससे अस्पताल का सबसे प्रमुख अंग सर्जरी ओ.टी. प्रभावित है;

(ख) क्या यह सही है कि अस्पताल में एक वर्ष पहले यह सी-आर्म मशीन खरीदी गई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण इस मशीन को रखने के लिए टेबुल की खरीदारी नहीं हो रही है; जिससे यह मशीन खराब होने की स्थिति में है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपकरण आपूर्ति कर्त्ता बी.एम. एस.आई.सी.एल. का इंतजार किये बिना, देरी होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर टेंडर तुरंत कराने और इसके सहायक उपकरण की खरीदारी करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

चिकित्सा की व्यवस्था

***25 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार राज्य के पूर्व निर्धारित स्थानों पर ट्रामा सेंटर की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना के साथ इसे कार्यरूप में लाना चाहती है जिससे कि पीडि◌त जनों की त्वरित चिकित्सा संभव हो सके, यदि हां तो कबतक ?

बिजली की व्यवस्था

***26 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के उचकागांव के गद्दी टोला में ट्रांसफार्मर लगने के बाद लोग डेढ़ साल से भी अधिक बिजली से वंचित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गद्दी टोला में बिजली आपूर्ति कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

यदि उपयुर्क्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लटकते विद्युत तार को सीधा कर जान-माल की रक्षा करना चाहती है ? यदि हां तो कबतक ?

भुगतान पर विचार

***27 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

गन्ना उद्योग :-

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा सूगर मि□ल के पास जिला के 40 हजार किसानों की ईख की बकाया राशि 100 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि मि□ल के मुख्य महाप्रबंधक ने इस संबंध में किसानों की

समस्याओं पर चर्चा करते हुए किसान प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया था कि सीजन 2018 की दीपावली के पहले बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा परन्तु आजतक किसानों को ईख के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है;

(ग) क्या यह सही है कि किसानों को बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को ईख की बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

जल की आपूर्ति

***28 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

Education Minister :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण के नरकटियागंज अनुमंडल के साठी, लौरिया प्रखंड के गोबरौरा, मंझौलिया प्रखंड के सिरिसवा बाजार, नौतन प्रखंड के नौतन बाजार और योगापट्टी में पानी की टंकी लगाई गई है किन्तु उससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन पानी टंकियों को जनहित में पानी की आपूर्ति कराने योग्य बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

डायलिसिस की सुविधा

***29 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला के मुख्यालय में सदर अस्पताल है;

(ख) क्या यह सही है कि बक्सर सदर अस्पताल में किडनी डायलिसिस की सुविधा

नहीं होने से गरीब मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बक्सर सदर अस्पताल में किडनी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्युत की व्यवस्था

*30 **श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड की करहिया पूर्वी पंचायत के वार्ड नं.-6 के उपभोक्ता बांस-बल्ला लगाकर बिजली जलाने को मजबूर हैं चूंकि इनके घरों में बिजली तार लगाने के लिए सीमेन्ट का पोल नहीं गाड़ा गया है, जिससे हमेशा जान-माल का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक पोल गाड़कर विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है ?

डॉक्टर की नियुक्ति

*31 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दांत के मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से डेन्टल डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की थी लेकिन परीक्षा परिणाम जारी होने के एक वर्ष बाद भी चयनित डॉक्टर सड़क पर भटक रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इनमें कई चिकित्सक वर्षों से संविदा पर नियुक्त हैं और अपनी सेवाएं बिहार सरकार को दे रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल्द से जल्द इन चयनित डेन्टल डॉक्टरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

***32 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सितम्बर, 2018 में ही एक मातृ एवं शिशु अस्पताल की स्थापना की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक-1031(10), दिनांक-1.2.1019 द्वारा उस अस्पताल के बजट और विभिन्न कोटि के पदों की स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि संजीवनी कार्यक्रम के तहत डाटा इंट्री ऑपरेटरों को दज्ञेड़कर अभी तक उक्त अस्पताल में विभिन्न कोटि के स्वीकृति पदों के विरुद्ध एक भी नियुक्ति नहीं की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि मातृ एवं शिशु अस्पताल में पिछले एक वर्ष से सदर अस्पताल, शिवहर के कमियों से ही काम लिया जा रहा है जबकि पहले से ही उक्त अस्पताल मेूं कमियों की कमी है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मातृ एवं शिशु अस्पताल के लिए कमियों के स्वीकृत पदों पर कबतक बहाली कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नियमावली बनाने पर विचार

***33 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि आई.जी.आई.सी.-02/2019 ज्ञापांक-1102, दिनांक-16.08.2019 के द्वारा Open Heart सर्जरी में सहयोग हेतु महत्वपूर्ण Perfusionist के चार पद स्वीकृत हैं; (ख) क्या यह सही है कि इन स्वीकृत पदों के लिए नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली नहीं बनी है; (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आई.जी.आई.सी. में Perfusionist के स्वीकृत पदों के लिए नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली बनाएगी, यदि हां तो कबतक ?

स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण

*34 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड अन्तर्गत रजौर टोला लक्ष्मीपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र (ए.पी.एच.सी.) की स्वीकृति उपरांत जमीन भी उपलब्ध कर एवं जिला पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन, बेगूसराय के द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर संचिका प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त (ए.पी.एच.सी.) के निर्माण होने से क्षेत्र के पिछड़ा, महादलित एवं अन्य निर्धन परिवार के हजारों व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा जो अबतक इससे वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र (ए.पी.एच.सी.) का शीघ्र निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

ट्रामा सेंटर का निर्माण

*35 **श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के +पो. प्रेमनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास लगभग तीन एकड़ जमीन है,

(ख) क्या यह सही है कि प्रेमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रून्न्ीसदैपुर से गुजरने वाली सड़क एन.एच.-77 के समीप है,

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के निवासियों के लिए बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु रून्न्ीसैदपुर प्रखंड स्थित ग्राम-प्रेमनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसके पास पर्याप्त जजमीन उपलब्ध है, उस पर भवन बनाकर ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित करने का इरादा रखती है, यदि हां तो ?

कर्तव्य का निर्वहन

*36 **श्री राजन कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के देव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर एवं ए.एन.एम. महीना में एक या दो बार ही रहते ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंड के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित डॉक्टर एवं ए.एन.एम. के नहीं रहने के कारण प्राथमिक उपचार एवं जटिल रोग का इलाज कराने हेतु शहर के निजी क्लिक पर जाना पड़ता है, जिससे मरीजों का आर्थिक दोहन होना पड़ता ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित रूप से डॉक्टर एवं ए.एन.एम. से कर्तव्य का निर्वहन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो ?

दोषी पर कार्रवाई

*37 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

उद्योग क्या माननीय मंत्री उद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि। (क) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण यहां के उद्योग पति को काफी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा हैं। (ख) क्या यह सही है कि उद्योग पतियों के द्वारा सब्सिडी भुगतान राशि के लिए समय से प्रोसेस करने के बाद भी विभाग का चक्कर काटना पड़ता है फिर भी सब्सिडी राशि समय पर नहीं मिल पा रहा। (ग) क्या यह सही है कि सब्सिडी भुगतान राशि की फाइल उद्योग विभाग में धूल फांक रहा है जैसे कि देवघर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जमुई का सब्सिडी राशि भुगतान नहीं होने के कारण मिलर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। (घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हे तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों।

जागरूकता लाने पर विचार

*38 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बीते दिन आयी बाढ़ एवं जल-जमाव वाले क्षेत्रों में मच्छरों एवं डेंगू के प्रकोप से लोग त्रस्त हैं, लेकिन प्रखंड एवं जिला स्तर के अस्पतालों में मच्छरों एवं डेंगू से प्रभावित लोगों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है और इसके कारण पीडि़तों के इलाज के लिए परिजन राजधानी के अस्पतालों की ओर आने के लिए विवश हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जून 2018 में डेंगू एवं चिकुनगुनिया के प्रति जागरूकता हेतु राज्य के पटना, नालन्दा, वैशाली, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में माइकिंग रिक्शा परिचालन सितम्बर माह 2018 तक किया गया था, किन्तु विभागीय सुस्ती के कारण इसका प्रचार-प्रसार बंद है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सघन अभियान चलाकर जिला एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करने एवं डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति कर डेंगू एवं चिकुनगुनिया से पीडि़त लोगों का उपचार कराने तथा इसके प्रति जागरूता लाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

***39 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में 16 पंचायतों में 1 लाख 90 हजार की आबादी बसर करती है;

(ख) क्या यह सही है कि 2016 में बरौली मुख्यालय में सरकार के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण कराने का आदेश जारी किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरौली प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करायेगी, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जलापूर्ति योजना

***40 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

Education Minister :-

क्या माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करना चाहेंगे की:-

खण्ड - (क)- क्या यह सही है कि बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के 70 गाँवों को आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से बहुद्देशीय ग्रामीण पाईप लाइन जलापूर्ति योजना कार्य की निविदा आई० वी० आर० सी० एल० कम्पनी को दिया गया था ?

खण्ड - (ख)- क्या यह सही है की ठेकेदार एवं विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से कार्य कराये बिना हीं इस योजना की 80 प्रतिशत राशि निकाल ली गयी है ?

खण्ड - (ग)- क्या यह सही है की ठेकेदार एवं विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही एवं संवेदनहीनता के चलते सिमरी प्रखंड के 70 गांवों की आबादी आज भी आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर है ?

खण्ड - (घ)- अगर उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस योजना का निर्माण कार्य पूरा कराने एवं दोषी संवेदक तथा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?

जलमीनार का उपयोग कबतक

***41 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

Education Minister :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से सीतामढ़ी जिला में 46 जलमीनारों का निर्माण पांच वर्ष पूर्व किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित जलमीनारों से कहीं भी जलापूर्ति नहीं जा सकी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जलमीनारों का उपयोग जल-नल योजना में करने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के तो इस योजना के तहत एक भी जलमीनार का उपयोग अबतक नहीं किए जाने का क्या औचित्य है ?

विद्युत कनेक्शन देने पर विचार

***42 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड सं.-30, मुहल्ला-हरिश्चन्द्र नगर, सिपारा (कृषि फॉर्म के दक्षिण) नया ढ़लाई रोड के किनारे लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर के पश्चिम बिजली का पोल एवं तार जर्जर स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि रेल लाईन के बगल में 8-9 महीना से नया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया है तथा कवर्ड तार भी लगा दिया गया है, लेकिन वहां के आवासित घरों में कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित मुहल्ला में नया ढलाई रोड के किनारे आवासित लोगों के घरों में कवर्ड तार द्वारा विद्युत कनेक्शन देने तथा पुराने जर्जर पोल एवं तार को अतिशीघ्र हटाना चाहती है ?

जान-माल की रक्षा

***43 श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड की सुगौना उत्तरी पंचायत के जहरमोहरा ग्राम के वार्ड नं.-15 में विद्युत तार गांव के ब्राह्मण टोला में लटक रहा है, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रामीण अपने घरों के सामने बांस का खंभा लगाकर खतरा से बचने का प्रयास करते रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लटकते विद्युत तार को सीधा कर जान-माल की रक्षा करना चाहती है ?यदि हां तो कबतक ?

दोषी पर कार्रवाई

***44 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है एवं अस्पतालों में भी

बिजली के कनेक्शन हैं और आपूर्ति भी नियमित है इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में गया जिले में सरकारी अस्पतालों में जेनरेटर मद में करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नवंबर, 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर केस नंबर 16211/17 में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मगध के प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने मामले की जांच की इस टीम में मगध के क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं गया के अपर जिला दंडाधिकारी भी शामिल थे, टीम ने 26 जून, 2019 को अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी, जांच में कुल दो करोड़ 24 लाख रुपये की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ परन्तु आजतक दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल्द से जल्द दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

नीरा का निर्माण

***45 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

उद्योग :-

क्या मंत्री उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क) क्या यह सही है कि राज्य में पूर्ण शराब बंदी के बाद सरकार द्वारा ताड़ी के व्यवसाय से जीविका चलाने वाले पासी समाज के लोगों को ताड़ी का व्यवसाय करने पर भी रोक लगा दी गयी है,

ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि राज्य में ताड़ के पेड़ से नीरा निकाल कर उससे गुड़,जलेबी आदि कई उत्पाद बनेंगे तथा ताड़ी का व्यवसाय करने वाले लोग मालामाल हो जायेंगे,

ग) क्या यह सही है कि बिहार विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2017-2018 की बजटीय मांग पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी कि सरकार द्वारा नीरा का उत्पादन कराने हेतु हाजीपुर,भागलपुर,नालंदा और गया में कारखाना स्थापित कर लिया गया है जिसमें 15 अप्रील 2018 से उत्पादन शुरू हो जायेगा ,

घ) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा घोषित नीरा निर्माण के उक्त कारखाने के निर्माण एवं स्थापना के नाम पर सरकारी राशि का भारी गबन और लूट-खसोट किया

गया है तथा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उत्पादन शून्य है एवं पासी समाज के लोग भूखों मरने को विवश हैं,

ङ) यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पासी समाज के लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु अपनी घोषित योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में नीरा का उत्पादन करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?